4867

सीमा सुरक्षा सैनिकों पर गोलाबारी की थी:

- (ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप आन व माल की कितनी हानि हुई; भीर
- (ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रो (भी यशवन्तराव बन्हाच) : (क) पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने 8, 9 मौर 10 दिसम्बर, 1966 को बेलोनिया पर तथा उसके चारों भ्रोर मास पास रक-रक कर गोलाबारी की थी।

- (ख) जान व माल की हानि की कोई सूचना प्राप्त नही हुई।
- (ग) किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने के लिये कारगर उपाय प्रपनाये गये हैं, श्रीर पूर्वी पाकिस्तान राइफन्स के सैनिकों को गोलाबारी करने से रोकने के लिये लगातार कोशिशें की गई 8 1

Public Sector Undertakings

2328. Shri S. R. Damani: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that I.A.S. officials have been deputed to the public sector undertakings;
- (b) if so, the number of such officials serving the different public sector undertakings at present; and
 - (c) the tenure of such deputations?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

International Commission of Jurists

2329. Shri George Fernandes:

Shri J. H. Patel:

Shri A. Sreedharan: Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

- (a) whether the International Commission of Jurists have, in a declaration published in their Bulletin issued from Geneva in March, April, 1967, criticised the Government of India for "suppression of basic human rights" in India; and
- (b) the steps Government propose to take in this regard?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) Government have seen the article on "Inroads into Fundamental Rights in India" in the March, 1967 issue of the Bulletin of the International Commission Jurists.

(b) Government have explained in Parliament from time to time their policies regarding the Preventive Detention Act and the state of emergency. No further action is considered necessary.

हिस्सी में कर्मों से प्राप्त गैर-कानुनी हस्ताबेज

2330. भी हकम चन्द कछवाय : भी जगन्नाय राव जोशी:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि मप्रैल, 1967 में दिल्ली के चावडी बाजार में लोहे के सामान की एक फर्म तथा छः ग्रन्य फर्मों में मारे गये छापों के दौरान गैर-कानुनी दस्तावेज पकडे गये थे :
- (ब) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं ;
- (ग) उन्होंने माय कर का कितना मपदंवन किया थाः धीर

(थ) इन फर्मों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी विद्या चरण शुक्ल): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन के बिकी कर प्राधिकारियों ने 7-4-67 को मेसर्स सरजभान ग्रग्रवाल ऐंड सन्स की फर्म, हार्डवयर मर्चेंटस, चावडी बाजार, दिल्ली एव उसके मालिक के निवास स्थान, चावडी बाजार दिल्ली में छापा मारा ग्रीर कुछ दस्तावेजो को कब्जे मे ले लिया। इन दस्तावेजो की जाच की जा रही है। फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न, तभी उठेगा जब दस्तावेज भादि की जाच के पश्चात यदि यह सिद्ध हम्रा कि व्यापारी ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली मे लाग बगाल वित्त (बिकी कर) अधिनियम के उपबन्धो के अधीन कुछ अनियमिताए की हैं। इसी प्रकार स्रायकर की स्रप्यचन की गई राशि, यदि कुछ है, केवल सम्बन्धित स्मयकर के मल्याकन-कार्यके पूरे होने पर जानी जा सकती हैं। अप्रैल, 1967 में ऐसी किसी दूसरी फर्म पर छापानही मारा गया था।

मंत्रियों के निजी सहायक (पर्सनस असिस्टेंट भीर सम्बद

2332 श्री विभूति मिश्र : श्री क० ना० तिवारी :

क्या गह-कार्य मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

- (क) क्या बह सच है कि केन्द्रीय मन्त्रिमडल के बर्गमान मिलयों ने अपने राज्यों तथा अपनी ही जाति के लोगों को अपने निजी महायक तथा सचित्र नियुक्त किया है;
- (स्त्र) यदि हा, तो इसके क्या कारण है ; भीर
- (ग) ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (बी विद्या घरण गुक्ल) (क) से (ग): मित्रयों को प्रपने निखी कर्मचारियों के चुनाव में स्वाधीनता है जिससे कि वे ऐसे व्यवितयों को चुन सके जिन पर उन्हें विश्वास हो। निजी कर्मचारियों द्वारा करायें जाने वासे कार्य की प्रकृति के कारण इस प्रकार की स्वाधीनता प्रावण्यक समझी गई है। फिर भी, प्रधिकतर मामलों में ऐसे पदो पर नियुक्त व्यक्ति किसी न किसी सगठित सेवा से सम्बन्ध रखते है।

Reimbursement of Expenses for Policing International Border

2333. Shri R. Barua: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

- (a) whether Government propose to reimburse the expenses incurred by the Government of Assam in policing the international border and in supplying food ration to the Police Forces sent to Assam by the Union Government; and
- (b) the break-up of these expenses from 1960 onwards?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). It will not be in the public interest to disclose the information asked for.

Unemployment among Engineers

2334. Shri Sradhakar Supakar; Shri N. R. Laskar; Shri Gunanand Thakur;

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:

- (a) whether there is a large scale unemployment and under-employment among the new Graduates and Overseers in most branches of Engineering; and
- (b) whether in many educational institutions, the intake of students per annum is being consequently reduced?

The Minister of State in the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a)